जाने वाले टोण्ड दूध का मूल्य 9-11-1993 से बराबर अर्थात् , 7.00 रुपये प्रति लीटर है । इससे पहले मदर डेयरी बैण्डिग मशीनों के माध्यम से 8.00 रुपये प्रति लीटर कीमत पर टोण्ड दूध बेच रही थी ।

(ख) और (ग) "दिल्ली दुग्ध योजना" सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राज्य डेयरी परिसंघों, सहकारी समितियों तथा निजी ठेकेदारों से दूध खरीद रही है । वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को 33.18 करोड़ रुपए की हानि हुई थी जिसकी वजह दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कीमत, उत्पादन लागत से कम होने के अलावा और कोई नहीं है और इसीलिए इसकी जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation on Plant Variety Protection

6049. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have initiated steps recently to bring about legislation quickly on the controversial issue of plant variety protection to fully safeguard the interests of farmers with regard to the use and availability of seeds in the wake of the new GATT agreements;

(b) if so, the important features contained in the proposed legislation to be brought forward by Government shortly; and

(c) by when Government is likely to bring forward the legislation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) A draft legislation for a sui-generis system for protection of plant varieties which is under preparation seeks to stimulate production of quality seeds, encourage Research and preserve the traditional right of the farmers to save, use, exchange, share and sell seeds except sale of branded seeds for commercial purpose. The draft legislation also seeks to protect existing varieties, and germplasm.

(c) The proposed sui-generis system will be brought forward for legislation after completion of due procedures required for the same.

DEBT Relief Scheme

6050. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh Government have claimed Rs. 100.37 crores under the Debt Relief Scheme; if so, what are the reasons for delay in the allocation of funds to the States; and

(b) whether the Central Government are aware that the State Government are not able to finance the agricultural plans because of non reimbursement of funds and if so, what steps are being taken to disburse funds to Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The details of the claims of cooperative banks in Uttar Pradesh under the Agricultural and Rural Debt Relief (ARDR) Scheme 1990 are given in enclosed statement. (*See* below)

(b) The implementation of plan schemes in agriculture is not linked to the release of amounts due to the State under the ARDR scheme, as plan schemes are funded separately.

A provision of Rs. 341 crores has been made in the budget for 1994-95 to

meet the balance claims of public sector banks, Regional Rural Banks and Coop. banks under the ARDR scheme. The release of the balance amount due to cooperative Banks in Uttar Pradesh will be considered after receipt of final revised claims from Uttar Pradesh State Cooperative Bank and U.P. State Land Development Bank duly complying with the instructions of NABARD for excluding ineligible claims and penal compound interest. Such revised claims have not yet been received by NABARD.

Statement

Details of claims of Co-operative Banks in Uttar Pradesh under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, '90

(Rs. in crores)

	Amount claimed	Amount sanctioned
U.P. State Cooperative Bank	543.173	481.594
U.P. State Land Development Bank . . .	102.156	89.546
TOTAL :	645.329	571.140

आम की नई शंकर किस्म का विकास

6051. श्री शारदा महन्ती :
श्री सोमपाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के पंजाब केसरी में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में वानगुरला स्थित कोंकण विद्यापीठ के क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र ने अल्फा सोरला नामक आम की गुठली रहित शंकर किस्म का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस किस्म की क्या विशेषताएं हैं और इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के लिए कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली द्वारा आम की सिंधु किस्म विकसित तथा रिलीज की गई है । इसे केवल विश्वविद्यालय स्तर पर जारी किया गया है न कि केंद्रीय किस्म रिलीज समिति के द्वारा । इस किस्म के फल की गुठली पतली करीब 7 ग्राम की होती है तो बिना गिरी/बीज के होती है और इस प्रकार इसे बीज रहित आम कहा जा सकता है । इसके फल अलफन्सो जैसे हैं, आम की यह किस्म संसाधन हेतु उपयुक्त है तथा स्पोन्जी ऊतक बीमारी से मुक्त है । इस किस्म की अखिल भारतीय समन्वित उपोष्ण अनुसंधान प्रायोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयुक्तता की बहुस्थानिक जांच के लिए रखा गया है, इसलिए फिलहाल पूरे भारत में इस किस्म के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।